वॉल्यूम 33, सं. 3, जनवरी, 2025

इंफोर्मेटिक्स

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रकाशित एवं ई गवर्नेंस बुलेटिन

Azadi Ka Amrit Mahotsav

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Digital India
Power To Empower

एनआईसी NIC

संपादकीय संयोजन : जी. वेंकू बाई

माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, श्री जी किशन रेड्डी ने 07 अगस्त 2024 को डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में खनन टेनमेंट प्रणाली के एफएमसीपी और अन्य लाइसेंस मॉड्यूल का उद्घाटन किया।

चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में ई-सनद पोर्टल लॉन्च किया गया

विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में 30 सितंबर 2024 को ई-सनद पोर्टल लॉन्च किया, जो दस्तावेज़ सत्यापन, सत्यापन और एपोस्टिल प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल इंडिया विज़न के अनुरूप इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उद्देश्य व्यक्तिगत और शैक्षिक दस्तावेज़ों के सत्यापन और एपोस्टिल की आवश्यकता वाले आवेदकों के लिए फेसलेस, कैशलेस और पेपरलेस सेवाएँ प्रदान करना है।

विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब सरकार के एनआरआई मामलों के विभाग के प्रिंसिपल श्री दिलीप कुमार, आईएएस और विशिष्ट अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक श्री संयम अग्रवाल, आईएएस उपस्थित थे। समारोह में एनआईसी और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए, जिनमें श्री आईपीएस सेठी, उप महानिदेशक और समूह प्रमुख, एमईए सूचना विज्ञान प्रभाग और श्री विवेक वर्मा, उप महानिदेशक और राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, पंजाब शामिल थे।

ई-सनद पोर्टल दस्तावेज़ सत्यापन की पारंपरिक रूप से बोझिल और समय लेने वाली प्रक्रिया को सरल बनाता है। आवेदकों को अब दस्तावेज़ जारी करने वाले अधिकारियों (डीआईए), राज्य सरकार के कार्यालयों या नई दिल्ली में एमईए में सीपीवी डिवीजन के कई चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय, वे पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं।

कार्यक्रम में बोलते हुए, श्री आईपीएस सेठी ने नागरिक-केंद्रित डिजिटल पहलों का समर्थन करने में एनआईसी के प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला, इस बात पर जोर दिया कि ई-सनद किस तरह माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है। श्री राज कुमार टिक्कू, वरिष्ठ निदेशक (आईटी) द्वारा पोर्टल का विस्तृत प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया, जिसमें इसकी सहज कार्यक्षमता और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों दोनों के लिए इसके लाभों को प्रदर्शित किया गया।

पंजाब सरकार ने सितंबर 2024 तक सभी जिलों में व्यक्तिगत दस्तावेजों के लिए ई-सनद को पूरी तरह से लागू कर दिया है। संचालन के सिर्फ़ एक महीने में, पोर्टल ने लगभग 5,700 आवेदनों को संसाधित किया, जिनमें से 3,200 को डीआईए और एनआरआई मामलों के विभाग द्वारा सत्यापित किया गया और 2,300 को विदेश मंत्रालय द्वारा प्रमाणित और एपोस्टिल किया गया।

चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उत्तर भारत में शैक्षणिक दस्तावेज़ सत्यापन के लिए ई-सनद प्लेटफ़ॉर्म अपनाने वाला पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है। यह मील का पत्थर छात्र कल्याण और तकनीकी उन्नति के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख लोगों में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) मनप्रीत सिंह मन्ना और सांसद (राज्यसभा) श्री सतनाम सिंह संधू शामिल थे, जिन्होंने छात्रों को सशक्त बनाने और विदेश में शिक्षा और रोजगार के प्रशासनिक बोझ को कम करने की पहल की क्षमता की प्रशंसा की।

- परमिंदर कौर, पंजाब

सिक्किम के पहले निःशुल्क वाई-फ़ाई गांव का उद्घाटन रबदांग में हुआ

डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सिक्किम ने 1 अक्टूबर, 2024 को रबदांग में अपने पहले निःशुल्क वाई-फ़ाई गांव का उद्घाटन किया है। माननीय सड़क और पुल मंत्री नर बहादुर दहल ने समारोह का नेतृत्व किया, जिसने राज्य में डिजिटल विभाजन को पाटने में एक मील का पत्थर साबित हुआ।

गंगटोक से 40 किमी और सिंगताम से 10 किमी दूर स्थित, 17-खामडोंग-सिंगताम निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा, रबडांग गांव में 72 घर हैं और इनकी आबादी लगभग 500 है। अब हर घर में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध होने के साथ, इस पहल का उद्देश्य गांव को व्यापक डिजिटल दुनिया से जोड़ना है, जिससे शिक्षा, व्यवसाय और संचार के अवसर खुलेंगे।

माननीय मंत्री ने इस परियोजना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एनआईसी सिक्किम की सराहना की। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा, "यह पहल केवल कनेक्टिविटी के बारे में नहीं है; यह हमारे ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने और उन्हें आज के डिजिटल परिदृश्य में पनपने के लिए उपकरणों से लैस करने के बारे में है।"

अपने शांत परिदृश्य और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाने वाला, सिक्किम, भारत का सबसे कम आबादी वाला और दूसरा सबसे छोटा राज्य, डिजिटल समावेशन में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। रबडांग को इंटरनेट एक्सेस से लैस करके, राज्य अपनी अनूठी पहचान को बनाए रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

निःशुल्क वाई-फाई गांव पहल समावेशी विकास को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है कि दूरदराज के समुदाय भी डिजिटल प्रगति से लाभान्वित हों। रबडांग की सफलता की कहानी अब अन्य गांवों के लिए एक प्रेरक मॉडल के रूप में सामने आई है, जो प्रौद्योगिकी के माध्यम से शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटने के लिए सिक्किम के समर्पण की पुष्टि करती है।

माननीय सड़क और पुल मंत्री नर बहादुर दहल ने सिक्किम के पहले निःशुल्क वाई-फ़ाई गांव के शुभारंभ के दौरान रबदांग गांव में समुदाय को संबोधित किया और डिजिटल शासन की परिवर्तनकारी शक्ति पर ज़ोर दिया।

माननीय मंत्री ने अपने दौरे के समापन पर, रबडांग के निवासियों ने न केवल इंटरनेट सेवाओं के आगमन का जश्न मनाया, बल्कि एक अधिक जुड़े और सशक्त भविष्य के वादे का भी जश्न मनाया।

- डॉ. लक्ष्मी प्रसाद शर्मा, सिक्किम

साइबराबाद पुलिस ने निर्बाध आयोजन अनुमोदन के लिए डिजिटल अनुमति प्रबंधन प्रणाली शुरू की

साइबराबाद पुलिस अनुमति प्रबंधन प्रणाली (CPPMS), एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जिसे नागरिकों और अधिकारियों दोनों के लिए इवेंट अनुमतियों को सरल बनाने और दक्षता में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो आधिकारिक तौर पर तेलंगाना में 13 अक्टूबर, 2024 को लॉन्च किया गया। एन आई सी द्वारा विकसित, यह उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफ़ॉर्म भौतिक सबमिशन की पारंपरिक प्रक्रिया को बदल देता है, जिससे इवेंट आयोजकों को आवश्यक परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में मदद मिलती है।

नया पोर्टल आयोजकों को एक ही इंटरफ़ेस के ज़रिए सभी ज़रूरी अनुमतियों के लिए आवेदन जमा करने की सुविधा देता है, जिससे कई दफ़्तरों में जाने की ज़रूरत खत्म हो जाती है और कागजी कार्रवाई और देरी में काफ़ी कमी आती है।

समय पर प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवेदन कम से कम 10 कैलेंडर दिन या 7 कार्य दिवस पहले जमा किए जाने चाहिए। साइबराबाद पुलिस अधिकारियों ने कहा, "अनुमति एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर दी जाएगी, और देरी के मामले में, अनावश्यक देरी को रोकने के लिए आवेदन स्वचालित रूप से उच्च अधिकारियों तक पहुँच जाएँगे।"

साइबराबाद पुलिस अनुमति प्रबंधन प्रणाली अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के साथ इवेंट आयोजकों को सशक्त बनाता है, जबकि अधिकारियों को अनुमोदन का प्रबंधन करने के लिए एक कुशल, केंद्रीकृत प्रणाली प्रदान करता है। यह पहल तेलंगाना के शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

इस लॉन्च के साथ, साइबराबाद ने पुलिस सेवाओं में पारदर्शिता, पहुँच और दक्षता में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे नागरिकों के लिए परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित होता है।

साइबराबाद पुलिस अनुमति प्रबंधन प्रणाली (CPPMS) को साइबराबाद पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती ने 13 अक्टूबर, 2024 को शुरू किया

- रेनिल जॉन, हैदराबाद

पीएमईड्राइव(PMeDRIVE) फेस रिकग्निशन सिस्टम इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) सब्सिडी वितरण में लाभार्थी की पहचान में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा

सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, भारत सरकार की पहल में अपनी तरह का पहला पीएमईड्राइव (PMeDRIVE) फेस रिकग्निशन सिस्टम का अनावरण 3 अक्टूबर 2024 को किया गया है। यह अत्याधुनिक तकनीक आधार फेस eKYC करने के लिए एक सरल Android स्मार्टफ़ोन का लाभ उठाती है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की खरीद के लिए सटीक लाभार्थी की पहचान और निर्बाध सब्सिडी वितरण संभव हो पाता है।

मानक मोबाइल कैमरे का उपयोग करके व्यक्तियों को पहचानने की प्रणाली की क्षमता जटिल हार्डवेयर की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे यह लागत-प्रभावी और उपयोगकर्ता के अनुकूल दोनों बन जाती है। यह नवाचार सार्वजनिक सेवाओं में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

इस अवसर पर बोलते हुए, भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव ने डिजिटल नवाचार में अग्रणी योगदान के लिए एनआईसी की सराहना की और कहा कि पीएमईड्राइव फेस रिकग्निशन सिस्टम शासन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए एक नया मानदंड स्थापित करता है।

लाभार्थियों की सटीक पहचान सुनिश्चित करके, पीएमईड्राइव (PMeDRIVE) प्रणाली विसंगतियों को दूर करती है और इलेक्ट्रिक वाहन खरीद योजना के तहत सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया को गति देती है। यह पहल न केवल ईवी को अपनाने को बढ़ावा देती है, बल्कि एक टिकाऊ और कुशल भविष्य को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के सरकार के दृष्टिकोण का भी उदाहरण है।

भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव श्री कामरान रिज़वी कार्यक्रम के दौरान पीएम ई-ड्राइव के फायदे बताते हुए।

इस अभूतपूर्व विकास के साथ, भारी उद्योग मंत्रालय, एनआईसी के सहयोग से, अभिनव और पारदर्शी डिजिटल समाधानों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

- अर्चना शर्मा, एनआईसी-मुख्यालय

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने 153 वेबसाइटों को NIC के S3WaaS फ्रेमवर्क में माइग्रेट किया

पहुँच, सुरक्षा और नागरिक-केंद्रित सूचना प्रसार को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, 153 केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) वेबसाइटों को NIC द्वारा विकसित S3WaaS फ्रेमवर्क में सफलतापूर्वक माइग्रेट किया गया है।

S3WaaS (सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य वेबसाइट एज़ ए सर्विस) प्लेटफ़ॉर्म वेबसाइट विकास के लिए एक मज़बूत और उपयोगकर्ता के अनुकूल समाधान प्रदान करता है, जो सरकारी संस्थाओं को दक्षता और समावेशिता हेतु डिज़ाइन किए गए उपयोग के लिए तैयार टेम्पलेट प्रदान करता है।

यह माइग्रेशन सुनिश्चित करता है कि KVS वेबसाइट वैश्विक पहुँच मानकों के अनुरूप हों, जिससे विकलांगों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध पहुँच संभव हो सके। इसके अतिरिक्त, यह ढांचा संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाता है और बढ़ते ट्रैफ़िक और सामग्री की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मापनीयता सुनिश्चित करता है।

यह माइग्रेशन नागरिक-केंद्रित शासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। S3WaaS प्लेटफ़ॉर्म को अपनाकर, KVS सूचना प्रसार को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे छात्रों, अभिभावकों और हितधारकों को अपडेट और आवश्यक विवरण आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं।

NIC सरकारी संस्थानों को अभिनव डिजिटल समाधानों के साथ सशक्त बनाने, पारदर्शिता और पहुँच को बढ़ावा देते हुए देश के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

- हेमेंद्र कुमार सैनी, एनआईसी-मुख्यालय

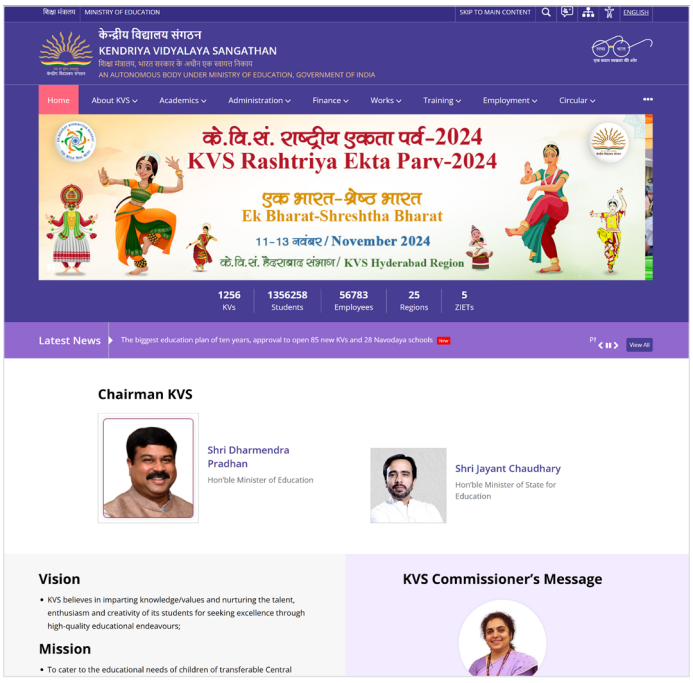

जीएसटी ई-इनवॉयस प्रणाली ने भारत में कर अनुपालन में परिवर्तन के 4 वर्ष पूरे किए

भारत के कर प्रशासन में एक ऐतिहासिक पहल, जीएसटी ई-इनवॉइस सिस्टम ने अपनी 4वीं वर्षगांठ मनाई, जो व्यवसायों के लिए कर अनुपालन को सरल और डिजिटल बनाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। अक्टूबर 2020 में लॉन्च की गई इस प्रणाली ने चालान बनाने और रिपोर्टिंग में क्रांतिकारी बदलाव किया है, पारदर्शिता को बढ़ाया है, कर चोरी को कम किया है और करदाताओं और सरकार दोनों के लिए संचालन को सुव्यवस्थित किया है।

पिछले चार वर्षों में, ई-इनवॉइस प्रणाली को उद्योगों में व्यापक रूप से अपनाया गया है, जिससे व्यवसायों को वास्तविक समय में चालान सत्यापन और जीएसटी प्रणालियों के साथ सहज एकीकरण का अधिकार मिला है। इससे न केवल मैनुअल हस्तक्षेप कम हुआ है, बल्कि त्रुटियों को भी कम किया गया है, जिससे कर रिपोर्टिंग में सटीकता और दक्षता सुनिश्चित हुई है।

ई-इनवॉइस प्रणाली डिजिटल इंडिया मिशन की आधारशिला है, जो कागज रहित और प्रौद्योगिकी-संचालित अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन को बढ़ावा देती है। इसकी विशेषताओं में जीएसटी पोर्टल पर स्वचालित रिपोर्टिंग, व्यवसायों में अंतर-संचालन और कर अधिकारियों द्वारा बेहतर अनुपालन निगरानी शामिल है।

सिस्टम की सफलता पर प्रकाश डालते हुए, एक वरिष्ठ जीएसटीएन अधिकारी ने कहा, "जीएसटी ई-इनवॉइस सिस्टम ने कर अनुपालन परिदृश्य को बदल दिया है, जिससे यह व्यवसायों के लिए सरल और अधिक कुशल हो गया है। जैसा कि हम इस पहल के चार साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, हम बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।"

उपलब्धियाँ और आगे की राह

• **बेहतर अनुपालन:** दस लाख से ज़्यादा चालान बनाए गए हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है।

• **व्यापार करने में आसानी:** सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं ने व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ को कम कर दिया है।

• **भविष्य के नवाचार:** सिस्टम की क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए उन्नत एनालिटिक्स और एआई-संचालित समाधानों को एकीकृत करने की योजनाएँ चल रही हैं।

जैसे-जैसे जीएसटी ई-इनवॉइस सिस्टम अपने पांचवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, यह शासन को बदलने और डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी की शक्ति का प्रमाण बन रहा है।

- अर्चना शर्मा, एनआईसी-मुख्यालय

कर्नाटक की ई-जन्म ने डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में क्रांति ला दी है

एनआईसी ने 10 सितंबर 2024 को लद्दाख के कारगिल जिले में 'ई-सक्ष्य ऐप' पर एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस पहल में कारगिल क्षेत्र के सभी स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ), जांच अधिकारी (आईसी) और प्रिंसिपल पुलिस स्टाफ (पीपीएस) सहित 60 से अधिक पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। एनआईसी अधिकारियों ने ऐप की विशेषताओं और कार्यात्मकताओं पर प्रकाश डालते हुए विस्तृत प्रस्तुतियाँ दीं, जिसका उद्देश्य पुलिस संचालन की दक्षता बढ़ाना था।

एक समानांतर पहल में, एनआईसी ने चोगलामसर में जिला पुलिस लाइन्स में लेह पुलिस के अधिकारियों के लिए 'ई-साक्ष्य ऐप' पर एक प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया। इस सत्र में डीएआर के लिए पुलिस उपाधीक्षक (डिप्टी एसपी), जिला पुलिस लाइन के रिजर्व इंस्पेक्टर, एसएचओ, आईसी, पीपीएस और लेह पुलिस के जांच अधिकारियों सहित प्रमुख कर्मियों ने भाग लिया।

'ई-सक्ष्य ऐप' को पुलिस बल के भीतर साक्ष्य प्रबंधन और केस हैंडलिंग की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, बेहतर समन्वय और महत्वपूर्ण जानकारी तक त्वरित पहुँच की सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस डिजिटल उपकरण का उपयोग करने के लिए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करके, एनआईसी का लक्ष्य कानून प्रवर्तन प्रभावशीलता को बढ़ाना और पुलिस प्रणाली के भीतर पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।.

दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रम कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रौद्योगिकी के साथ सशक्त बनाने के लिए

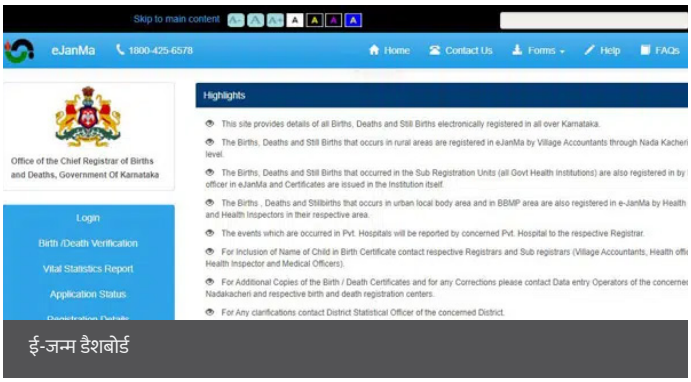

ई-जन्म डैशबोर्ड

एनआईसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं, जिससे सेवा वितरण में सुधार होता है और लद्दाख के नागरिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा मिलता है।

- बी.पी. श्रीनिवासन, कर्नाटक

देशभर में ई-शासन गतिविधियों के बारे मे नवीनतम व अद्यतन समाचारों व सूचना के लिये News पर जाये https://informatics.nic.in/news